



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1566।

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 17, 2012/श्रावण 26, 1934

No. 1566।

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 17, 2012/SHRAVANA 26, 1934

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2012

(आय-कर)

का.आ. 1877(अ).—चूंकि करों के संबंध में सूचनाओं के आदान-प्रदान तथा उसके संग्रहण में सहायता के लिए भारत गणराज्य की सरकार और लाइब्रेरिया गणराज्य की सरकार के बीच लाइब्रेरिया में 3 अक्टूबर, 2011 को संलग्न अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे।

और चूंकि, उपर्युक्त अनुबंध के प्रवृत्त होने की तारीख 30 मार्च, 2012 है, जो कि उपर्युक्त अनुबंध के अनुच्छेद 12 के अनुसार, अनुबंध को लागू करने के लिए संबंधित देशों के कानूनों के द्वारा यथा अपेक्षित प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद अधिसूचनाओं में से बाद की अधिसूचना की तारीख है।

इसलिए, अब, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि इसके साथ संलग्न उपर्युक्त अनुबंध के सभी उपबंध भारत संघ में दिनांक 30 मार्च, 2012 से लागू होंगे।

[अधिसूचना सं. 32/20012-एफटी एंड टीआर-II/फा. सं. 503/02/2010-एफटी एंड टीआर-II]

के. रामलिंगम, संयुक्त सचिव

करों के संबंध में सूचना के आदान-प्रदान
तथा वसूली में सहायता हेतु

भारत गणराज्य की सरकार

और

लाइबेरिया गणराज्य की सरकार

के बीच करार

भारत गणराज्य की सरकार और लाइबेरिया गणराज्य की सरकार, करों के संबंध में सूचना के आदान-प्रदान तथा वसूली में सहायता को सुकर बनाने की इच्छा से निम्नानुसार सहमत हुए हैं :

अनुच्छेद 1
करार का उद्देश्य एवं कार्य-क्षेत्र

संविदाकारी पक्षों के सक्षम प्राधिकारी सूचना के आदान-प्रदान के माध्यम से, जो कि इस करार के अंतर्गत आने वाले करों के संबंध में संविदाकारी पक्षों के घरेलू कानूनों के प्रशासन एवं प्रवर्तन से संगत हैं, सहायता उपलब्ध कराएंगे। ऐसी सूचना में वह जानकारी शामिल होगी जो ऐसे करों के निर्धारण, मूल्यांकन और वसूली, कर दावों की वसूली और प्रवर्तन अथवा कर मामलों की जांच-पड़ताल या अभियोजन के लिए सुसंगत हैं। इस करार के उपबंधों के अनुसार सूचना का आदान-प्रदान किया जाएगा। सक्षम प्राधिकारी कर दावों के संग्रहण में एक-दूसरे को सहायता भी प्रदान करेंगे। अनुरोधित पक्ष के कानूनों अथवा प्रशासनिक प्रथा द्वारा व्यक्तियों को प्राप्त कराए गए अधिकार और रक्षोपाय उस सीमा तक प्रयोज्य रहेंगे जहाँ तक कि वे सूचना के प्रभावी आदान-प्रदान अथवा वसूली में सहायता में अनुचित रूप से बाधा न डाले अथवा उसे विलम्बित न करें।

अनुच्छेद 2

क्षेत्राधिकार

सूचना का आदान-प्रदान इस करार के अनुसार किया जाएगा, इस बात का ध्यान किए बिना कि वह व्यक्ति जिससे यह सूचना संबंधित है अथवा जिसके द्वारा सूचना धारित की गई है, किसी एक संविदाकारी पक्ष का निवासी है। तथापि, अनुरोधित पक्ष ऐसी सूचना को उपलब्ध कराने के लिए बाध्यकारी नहीं है, जो न तो उसके प्राधिकारियों के पास है और न ही उन व्यक्तियों के पास अथवा नियंत्रण में है, जो उसके राज्य-क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार में हैं।

अनुच्छेद 3

सम्मिलित कर

1. कर, जो इस करार के विषय है, में संविदाकारी पक्षों द्वारा करार पर हस्तांतर के समय लगाए गए प्रत्येक प्रकार तथा विवरण के कर हैं।
2. यह करार विद्यमान करों के अतिरिक्त अथवा उनके स्थान पर इस करार के हस्ताक्षरित होने की तारीख के बाद लगाए गए किन्हीं समरूप अथवा पर्याप्त रूप से समान करों पर भी लागू होगा। संविदाकारी पक्षों के सक्षम प्राधिकारी कराधान और संबंधित सूचना एकत्र करने वाले उपायों एवं वसूली उपायों में सहायता के संबंध में किन्हीं महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बारे में एक-दूसरे को अधिसूचित करेंगे, जो इस करार के अनुसरण में उस पक्ष की बाध्यताओं को प्रभावित कर सकते हैं।

अनुच्छेद 4

परिभाषाएं

1. इस करार के प्रयोजनार्थ, जब तक कि अन्यथा परिभाषित न किया जाए :

क) पद 'भारत' से तात्पर्य भारत का भू-क्षेत्र और इसमें सीमांतर्गत समुद्र और उसके ऊपर का हवाई क्षेत्र तथा कोई अन्य समुद्रवर्ती क्षेत्र है जिस पर भारतीय कानून के अनुसार तथा समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र के अभिसमय सहित अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार भारत का प्रभुत्वता सम्पन्न अधिकार, अन्य अधिकार और क्षेत्राधिकार है;

ख) पद 'लाइबेरिया' से तात्पर्य, वेस्ट अफ्रीका में अवस्थित तथा लाइबेरिया गणराज्य से है;

ग) पद 'संविदाकारी पक्ष' से तात्पर्य भारत अथवा लाइबेरिया, जैसा भी संदर्भ के अनुसार अपेक्षित होता है, से है;

घ) पद 'सक्षम प्राधिकारी' से तात्पर्य -

(i) भारत के भासले में, वित्त मंत्री, भारत सरकार अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि हैं;

(ii) लाइबेरिया के भासले में, वित्त मंत्री अथवा उसके प्राधिकृत प्राधिकारी;

ड.) पद 'व्यक्ति' में कोई व्यक्ति, कोई कम्पनी, व्यक्तियों का निकाय और कोई अन्य सत्ता शामिल है जिसे संबंधित संविदाकारी पक्षों में प्रवृत्त कराधान कानूनों के तहत कराधेय इकाई के रूप में माना जाता है;

च) पद 'कम्पनी' से तात्पर्य कोई निगमित निकाय अथवा कोई सत्ता है जिसे कर प्रयोजनों के लिए एक निगमित निकाय माना जाता हो;

छ) पद 'सार्वजनिक रूप से व्यापार करने वाली कम्पनी' से तात्पर्य ऐसी किसी कम्पनी से है जिसके शेयरों का प्रमुख वर्ग किसी मान्यता-प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध है, बशर्ते उसके सूचीबद्ध शेयर सहज ही जनता द्वारा क्रय अथवा विक्रय किए जा सकते हों। शेयर 'जनता द्वारा' क्रय अथवा विक्रय तभी किए जा सकते हैं यदि शेयरों का यह क्रय अथवा विक्रय प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः निवेशकों के सीमित समूह तक ही प्रतिबंधित न हों;

ज) पद 'शेयरों का प्रमुख वर्ग' से तात्पर्य वोट देने की शक्ति और कम्पनी के मूल्य के बहुमत का प्रतिनिधित्व करने वाले शेयरों के वर्ग अथवा वर्गों से है;

झ) पद 'मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज' से तात्पर्य है - संविदाकारी पक्षों के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा सहमत किसी स्टॉक एक्सचेंज से है;

ज) पद "सामूहिक निवेश निधि अथवा योजना" से तात्पर्य सामूहिक निवेश के साधन से है, चाहे उसका कानूनी रूप कुछ भी हो;

ट) पद "सार्वजनिक सामूहिक निवेश निधि अथवा योजना" से तात्पर्य किसी सामूहिक निवेश निधि अथवा योजना से है बशर्ते कि ऐसी निधि अथवा योजना में यूनिटों, शेयरों अथवा अन्य हितों को जनता द्वारा सहज ही खरीदा, बेचा अथवा पुनः प्राप्त किया जा सकता है। निधि अथवा योजना में यूनिटों, शेयरों अथवा अन्य हितों को "जनता द्वारा" सहज ही खरीदा, बेचा अथवा पुनः प्राप्त किया जा सकता है यदि ऐसी खरीद, बिक्री अथवा पुनः प्राप्ति प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः निवेशकों के सीमित समूह तक ही प्रतिबंधित न हो;

ठ) पद "कर" से तात्पर्य ऐसा कर है, जिस पर यह करार लागू होता है;

ड) पद "अनुरोध करने वाले पक्ष" से तात्पर्य, उस संविदाकारी पक्ष से है जो-

- (i) अनुरोधित पक्ष से सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध प्रस्तुत करता है; अथवा
- (ii) उनसे सूचना प्राप्त करता है; अथवा
- (iii) उनसे कर वसूली में सहायता के लिए अनुरोध प्रस्तुत करता है।

ढ) पद "अनुरोधित पक्ष" से तात्पर्य उस संविदाकारी पक्ष से है-

- (i) जिससे सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाता है अथवा
- (ii) जिसने सूचना उपलब्ध कराई है; अथवा
- (iii) जिससे कर की वसूली में सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया जाता है।

ण) पद "सूचना एकत्र करने वाले उपाय" से तात्पर्य कानूनी और प्रशासनिक अथवा न्यायिक कार्य प्रक्रियाओं से है जो किसी संविदाकारी पक्ष को अनुरोध की गई जानकारी प्राप्त करने और उपलब्ध कराने में सक्षम बनाते हैं;

३०६३६।।२-२

त) पद 'वसूली उपायों में सहायता' से तात्पर्य कानून तथा प्रशासनिक अथवा न्यायिक प्रक्रियाओं से है जो संविदाकारी पक्ष को अनुरोधित कर दावों की वसूली तथा छूट देने में सक्षम बनाती हैं।

थ) पद "सूचना" से तात्पर्य कोई तथ्य, विवरण, दस्तावेज अथवा रिकार्ड से है, चाहे वह किसी भी रूप में हो।

2. जहां तक किसी संविदाकारी पक्ष द्वारा किसी भी समय इस करार को लागू किए जाने का संबंध है, इसमें परिभाषित न किए गए किसी पद का, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, अथवा सक्षम प्राधिकारी इस करार के अनुच्छेद -10 के उपबंधों के अनुसरण में किसी आम अर्थ पर सहमत न हो, वही अर्थ होगा जो उस पक्ष के कानून के तहत उस समय हो, उस पक्ष के प्रयोज्य कर कानूनों के अंतर्गत कोई अर्थ उस पक्ष के अन्य कानूनों के तहत पद को दिए गए अर्थ की तुलना में अभिभावी रहता है।

अनुच्छेद 5

अनुरोध पर सूचना का आदान-प्रदान

1. अनुरोध किए जाने पर अनुरोधित पक्ष का सक्षम प्राधिकारी अनुच्छेद 1 में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए सूचना उपलब्ध कराएगा। ऐसी सूचना का आदान-प्रदान इस बात का विचार किए बिना किया जाएगा कि क्या अनुरोध करने वाले पक्ष को ऐसी सूचना की आवश्यकता अपने स्वयं के कर-प्रयोजनों के लिए है अथवा क्या वह आचरण जिसकी जांच-पड़ताल की जा रही है, वह अनुरोधित पक्ष के अंतर्गत अपराध होगा यदि ऐसा आचरण अनुरोधित पक्ष में घटित होता है।

2. यदि अनुरोधित पक्ष के सक्षम प्राधिकारी के आधिपत्य में कोई सूचना उस रूप में पर्याप्त नहीं है कि वह सूचना के लिए किए गए अनुरोध को पूरा करने में समर्थ हो तो वह पक्ष अनुरोधित सूचना को अनुरोध करने वाले पक्ष को उपलब्ध कराने के लिए सभी प्रासंगिक सूचना एकत्र करने के उपायों का प्रयोग करेगा, इस बात का ध्यान किए बिना कि अनुरोधित पक्ष को ऐसी सूचना की आवश्यकता अपने स्वयं के कर प्रयोजनों के लिए नहीं भी हो सकती है।

3. यदि अनुरोध करने वाले पक्ष के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से अनुरोध किया जाता है तो अनुरोधित पक्ष का सक्षम प्राधिकारी गवाहों के अभिसाक्ष्य तथा मूल रिकार्डों की अधिप्रमाणित प्रतियों के रूप में अपने घरेलू कानूनों के तहत अनुज्ञेय सीमा तक, इस अनुच्छेद के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराएगा।

4. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि उसके सक्षम प्राधिकारी को, इस करार के प्रयोजनार्थ अनुरोध पर निम्न को प्राप्त करने और उपलब्ध कराने का प्राधिकार है :

- क) बैंकों, अन्य वित्तीय संस्थानों, किसी एजेंसी अथवा न्यासी क्षमता में कार्य कर रहे किसी व्यक्ति, जिसमें नामजद व्यक्ति और न्यासी भी शामिल हैं, द्वारा धारित कोई सूचना;
- ख) कम्पनियों के कानूनी और लाभग्राही स्वामित्व, भागीदारी, सामूहिक 'निवेश निधियाँ अथवा स्कीमें, न्यासी, फाउंडेशन, 'आन्सटालटन' और अन्य व्यक्ति, संबंधी सूचना जिनमें अनुच्छेद 2 की सीमाओं के अंतर्गत किसी स्वामित्व श्रृंखला में सभी ऐसे व्यक्तियों की स्वामित्व सूचना; सामूहिक निवेश निधियों अथवा स्कीमों के मामले में, शेयरों, यूनिटों और अन्य हितों के बारे में सूचना; न्यासों के मामले में अवस्थापक, संरक्षकों न्यासियों और लाभभोगियों के संबंध में सूचना, संस्था के मामले में संस्थापकों, संस्था परिषद के सदस्यों और लाभग्राहियों के बारे में सूचना; और ऐसी सत्ताओं के बारे में ऐसी ही जानकारी जो न तो न्यास हैं और न ही संस्था है ।

5. यह करार सार्वजनिक रूप से व्यापार करने वाली कम्पनियों अथवा सार्वजनिक सामूहिक निवेश निधियों अथवा स्कीमों के संबंध में स्वामित्व संबंधी सूचना प्राप्त करने अथवा उपलब्ध कराने के लिए संविदाकारी पक्षों को बाध्य नहीं बनाती जब तक कि ऐसी सूचना विषम कठिनाईयाँ उत्पन्न किए बिना प्राप्त की जा सकती हो ।

6. अनुरोध करने वाले पक्ष के सक्षम प्राधिकारी अनुरोध के साथ सूचना की अनुमानित प्रासंगिकता का प्रदर्शन करने के लिए करार के तहत सूचना के लिए अनुरोध करते समय अनुरोध किए जाने वाले पक्ष के सक्षम प्राधिकारी को लिखित में निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराएंगे :

- क) जांच अथवा पूछताछ किए जाने वाले व्यक्ति की पहचान;
- ख) वह अवधि, जिसके लिए सूचना का अनुरोध किया गया है;
- ग) अनुरोध की गई सूचना का स्वरूप तथा वह प्रारूप जिसमें अनुरोध करने वाला पक्ष उसे प्राप्त करने को प्राथमिकता देगा;

घ) कर प्रयोजन जिसके लिए सूचना मांगी गई है;

घ.) यह विश्वास करने के कारण कि अनुरोध की गई सूचना अनुरोधित पक्ष के पास है अथवा अनुरोधित पक्ष के क्षेत्राधिकार के भीतर किसी व्यक्ति के अधिकार अथवा नियंत्रण में है;

घ) जहां तक संभव हो किसी व्यक्ति का नाम और पता, जिसके पास अनुरोधित सूचना होने अथवा उसके नियंत्रण में होने का अनुमान है;

घ) एक विवरण यह बताते हुए कि यह अनुरोध, अनुरोधकर्ता पक्ष के कानूनों और प्रशासनिक पद्धतियों के अनुरूप है, और यह कि यदि अनुरोधित सूचना अनुरोधकर्ता पक्ष के क्षेत्राधिकार में थी तो अनुरोधकर्ता पक्ष का सक्षम प्राधिकारी अनुरोधकर्ता पक्ष के कानूनों के तहत अथवा प्रशासनिक पद्धति की सामान्य प्रक्रिया के तहत सूचना प्राप्त करने में सक्षम होगा यह इस करार के अनुरूप है; और

ज) यह विवरण देते हुए कि अनुरोधकर्ता पक्ष ने सूचना को प्राप्त करने के लिए अपने स्वयं के राज्यक्षेत्र में उपलब्ध सभी साधन अपनाए हैं, सिवाए उनके, जो अत्यधिक कठिनाईयों को बढ़ाएंगे ।

7. अनुरोधित पक्ष का सक्षम प्राधिकारी शीमातिशीम अनुरोधित सूचना को अनुरोधकर्ता पक्ष को अग्रेषित करेगा । शीघ्र प्रत्युत्तर सुनिश्चित करने के लिए अनुरोधित पक्ष का सक्षम प्राधिकारी निम्न कार्य करेगा :

क) अनुरोधकर्ता पक्ष के सक्षम प्राधिकारी को लिखित में अनुरोध प्राप्ति की पुष्टि करेगा तथा अनुरोध की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर अनुरोध में कमियों के बारे में, यदि कोई हों, अनुरोधकर्ता पक्ष के सक्षम प्राधिकारी को अधिसूचित करेगा;

ख) यदि अनुरोधित पक्ष का सक्षम प्राधिकारी अनुरोध की प्राप्ति के 90 दिनों के भीतर सूचना को प्राप्त करने एवं प्रदान करने में असमर्थ होता है, जिसमें सूचना को प्रस्तुत करने में पेश आई बाधाएं शामिल हैं अथवा वह सूचना प्रदान करने से इंकार करता है तो वह तत्काल अपनी असमर्थता, बाधाओं के स्वरूप अथवा अपनी अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुरोधकर्ता पक्ष को सूचित करेगा ।

अनुच्छेद 6

विदेश में कर जांच

1. अनुरोधकर्ता पक्ष के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर अनुरोधित पक्ष, अनुरोधकर्ता पक्ष के सक्षम प्राधिकारी के प्रतिनिधियों को अपने अन्तरदेशीय कानूनों के तहत अनुमत्य सीमा तक, व्यक्तियों अथवा अन्य संबंधित व्यक्तियों की पूर्व लिखित सहमति से व्यक्तियों के साक्षात्कार हेतु और रिकार्डों की जांच करने के लिए अनुरोधित पक्ष के राज्यक्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दे सकता है। अनुरोधकर्ता पक्ष का सक्षम प्राधिकारी, संबंधित व्यक्तियों के साथ अभिप्रेत बैठक के समय एवं स्थान के बारे में अनुरोधित पक्ष के सक्षम प्राधिकारी को अधिसूचित करेगा।

2. अनुरोधकर्ता पक्ष के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर, अनुरोधित पक्ष, अनुरोधकर्ता पक्ष के सक्षम प्राधिकारी के प्रतिनिधियों को अनुरोधित पक्ष में कर जांच के उपयुक्त भाग में प्रत्युत रहने की अनुमति दे सकता है, जिस मामले में अनुरोधित पक्ष के जांच कर रहे सक्षम प्राधिकारी, जांच के संबंध में समय एवं स्थान, जांच करने के लिए प्राधिकारी अथवा नामोदिष्ट अधिकारी तथा जांच कार्य आरंभ करने के लिए अनुरोधित पक्ष द्वारा अपेक्षित शर्तों एवं प्रक्रियाओं के बारे में अनुरोधकर्ता पक्ष के सक्षम प्राधिकारी को शीघ्रातिशीघ्र अधिसूचित करेगा। कर-जांच करने के संबंध में सभी निर्णय जांच संचालित करने वाले पक्ष द्वारा किए जाएंगे।

अनुच्छेद 7

सूचना हेतु अनुरोध को अस्वीकार करने की संभावना

1. अनुरोधित पक्ष का सक्षम प्राधिकारी निम्न के संबंध में सहायता करने के लिए मना कर सकता है :

- क) जहां अनुरोध इस करार के अनुरूप नहीं किया गया हो; अथवा
- ख) जहां अनुरोधकर्ता पक्ष ने सूचना को प्राप्त करने के लिए अपने राज्यक्षेत्र में उपलब्ध सभी साधनों का अनुप्रयोग नहीं किया हो, सिवाय उनके जहां ऐसे साधनों का आश्रय लेने से अत्यधिक कठिनाई उत्पन्न होगी; अथवा
- ग) जहां सूचना का प्रकटन अनुरोधित पक्ष की लोक नीति (ऑर्डर पब्लिक) के प्रतिकूल होगा।

2. यह करार एक संविदाकारी पक्ष पर निम्न बाध्यता को अधिरोपित नहीं करेगा :

- i) ऐसी सूचना की आपूर्ति करने के लिए, जो किसी व्यापारिक, कारोबारी, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा व्यावसायिक गोपनीयता अथवा व्यापार प्रक्रिया को प्रकट करेगी, बशर्ते कि अनुच्छेद 5 के पैराग्राफ 4 में वर्णित सूचना को सिर्फ इस कारण से ऐसे गुप्त अथवा व्यापार प्रक्रिया के रूप में नहीं समझा जाएगा कि यह उस पैराग्राफ में वर्णित मापदण्ड को पूरा करती है; अथवा
- ii) ऐसी जानकारी प्राप्त करना अथवा प्रदान करना जो एक ग्राहक और एक अधिवक्ता और प्रतिवक्ता अथवा अन्य स्वीकृत कानूनी प्रतिनिधि के बीच गोपनीय संप्रेषणों को प्रकट करेगी, जहां ऐसे संप्रेषण :

 - क) कानूनी सलाह मांगने अथवा प्रदान करने के प्रयोजन से प्रस्तुत किए गए; अथवा
 - ख) वर्तमान अथवा अपेक्षित कानूनी प्रक्रियाओं में प्रयुक्त करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किए गए हों; अथवा

- iii) उनके कानूनों और प्रशासनिक प्रथाओं से हटकर प्रशासनिक उपायों को लान्सू करना बशर्ते कि इस उप-पैराग्राफ में ऐसा कुछ नहीं है जो अनुच्छेद-5 के पैराग्राफ-4 के तहत किसी संविदाकारी पक्ष की बाध्यताओं को प्रभावित करेगा।

3. सूचना हेतु अनुरोध को इस आधार पर मना नहीं किया जाएगा कि कर दावा जिसके कारण अनुरोध किया गया है, विवादित है।

4. अनुरोधित पक्ष से उस सूचना को प्राप्त करने अथवा प्रदान करने की अपेक्षा नहीं होगी जिसे अनुरोधकर्ता पक्ष अपने स्वयं के कानूनों के प्रशासन अथवा प्रवर्तन के प्रयोजन के लिए अपने कर कानूनों के तहत इसी तरह की परिस्थितियों में अथवा इस करार के तहत अनुरोधित पक्ष से वैध अनुरोध के प्रत्युत्तर में प्राप्त करने के लिए असमर्थ होगा।

5. अनुरोधित पक्ष किसी सूचना को देने से केवल इस कारण इंकार नहीं करेगा क्योंकि अनुरोध में अनुच्छेद 5 के तहत अपेक्षित सारी सूचना शामिल नहीं है यदि वह सूचना अनुरोधित पक्ष के कानून के अनुसार अन्यथा रूप से उपलब्ध कराई जा सकती है।

अनुच्छेद - 8
कर दावों की वसूली में सहायता

1. दोनों संविदाकारी पक्ष कर दावों की वसूली में एक दूसरे को सहायता देंगे ।
2. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त शब्द "कर दावा" का तात्पर्य अनुच्छेद 3 में यथा उल्लिखित करों के संबंध में देय कोई राशि तथा ऐसी राशि से संबंधित ब्याज, प्रशासनिक अर्थ-दंड और वसूली अथवा संरक्षण की लागत है ।
3. जब किसी संविदाकारी पक्ष का कर दावा उस पक्ष के कानूनों के अंतर्गत प्रवर्तनीय होता है और यह किसी व्यक्ति द्वारा देय होता है जो उस समय उस पक्ष के कानूनों के अंतर्गत इसकी वसूली को रोक नहीं सकता तब उस कर दावे को उस पक्ष के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर दूसरे संविदाकारी पक्ष के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा वसूली के प्रयोजनार्थ स्वीकार किया जाएगा । उस कर दावे को उस दूसरे पक्ष द्वारा अपने स्वयं के करों के प्रवर्तन और वसूली के लिए प्रयोज्य उसके कानूनों के उपबंधों के अनुसार वसूल किया जाएगा, मानो कि कर दावा उस दूसरे पक्ष का कर दावा था ।
4. जब किसी संविदाकारी पक्ष का कर दावा वह दावा है जिसके संबंध में वह पक्ष, अपने कानून के अंतर्गत इसकी वसूली को सुनिश्चित करने के लिए संरक्षण के उपाय करता है तब उस कर दावे को उस पक्ष के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर दूसरे संविदाकारी पक्ष के सक्षम प्राधिकारी द्वारा संरक्षण के उपाय करने के प्रयोजनार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा । दूसरा अन्य पक्ष उस कर दावे के संबंध में अपने कानूनों के उपबंधों के अनुसार संरक्षण के उपाय करेगा मानो कि कर दावे उस दूसरे पक्ष के कर दावे थे, यहां तक कि जब ऐसे उपायों का प्रयोग किया जाता है, कर दावा प्रथमोल्लिखित पक्ष में प्रवर्तनीय नहीं है अथवा उस व्यक्ति द्वारा देय है जिसे उसकी वसूली रोकने का अधिकार है ।
5. जब कोई संविदाकारी पक्ष अपने कानूनों के तहत, किसी व्यक्ति के प्रति किसी कर दावे को किए जाने से पहले परिसम्पत्तियों पर रोक लगाकर संरक्षणता का अंतरिम उपाय करता है तो दूसरे संविदाकारी पक्ष का सक्षम प्राधिकारी, यदि प्रथमोल्लिखित पक्ष के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुरोध किया जाता है, तो अपने देश के कानूनों के उपबंधों के अनुसार उस संविदाकारी पक्ष में उस व्यक्ति की परिसंपत्तियों पर रोक लगाने के लिए उपाय करेगा ।
6. पैराग्राफ 3 और 4 के उपबंधों के होते हुए भी पैराग्राफ 3 अथवा 4 के प्रयोजनार्थ किसी संविदाकारी पक्ष द्वारा स्वीकार किया गया कोई कर दावा उस राज्य में किसी समय

सीमा के अध्यधीन नहीं होगा अथवा उसी रूप में उसे इसके स्वरूप के कारण उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत किसी कर दावे को प्रयोज्य कोई प्राथमिकता नहीं दी जाएगी । इसके अलावा, पैराग्राफ 3 अथवा 4 के प्रयोजनार्थ किसी संविदाकारी पक्ष द्वारा स्वीकार किए गए कर दावे को उस राज्य में दूसरे संविदाकारी पक्ष के कानूनों के अंतर्गत उस कर दावे को प्रयोज्य कोई प्राथमिकता नहीं होगी ।

7. किसी संविदाकारी पक्ष के कर दावे के अस्तित्व, वैधता अथवा राशि के संबंध में कार्यवाही को केवल उस पक्ष के न्यायालयों अथवा प्रशासनिक निकायों के समक्ष लाया जाएगा । इस अनुच्छेद में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका यह अर्थ लगाया जाएगा कि दूसरे संविदाकारी पक्ष के किसी न्यायालय अथवा प्रशासनिक निकाय के समक्ष ऐसी कार्रवाहियाँ करने का अधिकार सृजित अथवा प्रदान करे ।

8. जहां, पैराग्राफ 3 अथवा 4 के तहत किसी संविदाकारी पक्ष द्वारा अनुरोध किए जाने के पश्चात् और प्रथमोल्लिखित पक्ष के संगत कर दावे को दूसरे संविदाकारी पक्ष में वसूल करने और प्रेषित करने से पहले संगत कर दावा वहां निम्नलिखित के संबंध में समाप्त हो जाएगा :

- क) पैराग्राफ 3 के अंतर्गत अनुरोध के मामले में, प्रथमोल्लिखित पक्ष का कोई कर दावा जो उस राज्य के कानूनों के तहत प्रवर्तनीय है और ऐसे व्यक्ति द्वारा देय है जो उस समय उस पक्ष के कानूनों के अंतर्गत इसकी वसूली रोक नहीं सकता; अथवा
- ख) पैराग्राफ 4 के अंतर्गत अनुरोध के मामले में, प्रथमोल्लिखित पक्ष के कर दावे जिसके संबंध में वह पक्ष अपने कानूनों के तहत इसकी वसूली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संरक्षण के उपाय करता है;

प्रथमोल्लिखित पक्ष का सक्षम प्राधिकारी इस तथ्य को दूसरे पक्ष के सक्षम प्राधिकारी को तत्काल अधिसूचित करेगा और दूसरे पक्ष के विकल्प पर प्रथमोल्लिखित पक्ष अपने अनुरोध को आस्थगित कर देगा अथवा हटा लेगा ।

9. किसी भी स्थिति में इस अनुच्छेद के उपबंधों का अर्थ किसी संविदाकारी पक्ष पर निम्नलिखित के लिए बाध्यता लागू करना नहीं लगाया जाएगा :

- क) उस संविदाकारी पक्ष अथवा दूसरे संविदाकारी पक्ष के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा से हटकर असंगत प्रशासनिक उपाय करना;
- ख) ऐसे उपाय करना जो लोक नीति (आर्डर पब्लिक) के विपरीत हों;

ग) सहायता प्रदान करना, यदि दूसरे संविदाकारी पक्ष ने इसके कानूनों अथवा प्रशासनिक प्रथा के अंतर्गत उपलब्ध वसूली अथवा संरक्षण, जैसा भी मामला हो, के सभी समुचित उपायों को न किया हो;

उन मामलों में सहायता प्रदान करना जहां उस राज्य के लिए प्रशासनिक बोझ दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लाभ से स्पष्ट रूप से अनुपातहीन हो ।

अनुच्छेद 9 विधान का कार्यान्वयन

संविदाकारी पक्ष करार की शर्तों का अनुपालन करने और उसे लागू करने के लिए किसी आवश्यक विधान को अधिनियमित करेंगे । ऐसे विधान को इस करार के प्रवृत्त होने के छह महीने के भीतर लागू किया जाएगा ।

अनुच्छेद 10 लागतें

सहायता प्रदान करने में उपगत लागत भार को संविदाकारी पक्षों द्वारा स्वीकार किया जाएगा ।

अनुच्छेद 11 पारस्परिक करार विधि

- जहां करार को कार्यान्वित करने अथवा उसकी व्याख्या करने के संबंध में संविदाकारी पक्षों के बीच कठिनाइयां अथवा संदेह उत्पन्न होते हैं वहां सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति से मामले को हल करने का प्रयास करेंगे । इसके अतिरिक्त, संविदाकारी पक्षों के सक्षम प्राधिकारी इस करार के अनुच्छेदों 5, 6 और 8 के तहत प्रयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं पर पारस्परिक रूप से सहमत होंगे ।
- संविदाकारी पक्षों के सक्षम प्राधिकारी इस अनुच्छेद के अंतर्गत करार करने के प्रयोजनार्थ एक-दूसरे से सीधे ही बातचीत करेंगे ।

अनुच्छेद 12 प्रवृत्त होना

- संविदाकारी पक्ष इस करार को प्रवृत्त करने के लिए अपने-अपने कानूनों के तहत अपेक्षित प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए राजनयिक माध्यम के जरिए लिखित में एक-दूसरे को अधिसूचित करेंगे ।

2. यह करार इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में उल्लिखित अधिसूचनाओं में से बाद की अधिसूचना की तारीख को लागू होगा और इसके बाद तुरंत प्रभावी होगा ।

अनुच्छेद 13

समापन

1. यह करार तब तक लागू रहेगा जब तक कि दोनों में से कोई एक संविदाकारी पक्ष इसे समाप्त नहीं कर देता है ।

2. दोनों में से कोई भी संविदाकारी पक्ष इसके लागू होने की तारीख से पांच वर्षों की समाप्ति के बाद राजनीतिक माध्यमों के जरिए दूसरे संविदाकारी पक्ष को समापन की एक लिखित सूचना भेज कर करार को समाप्त कर सकता है ।

3. इस तरह का समापन, दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा समापन के नोटिस की प्राप्ति की तारीख के बाद छह महीने की अवधि की समाप्ति के अनुवर्ती माह के प्रथम दिन को प्रभावी होगा । समापन की प्रभावी तारीख तक प्राप्त किए गए सभी अनुरोधों पर करार के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी ।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं ।

भोनरोविया, लाइबेरिया में वर्ष दो हजार र्यारह के अक्तूबर माह के तीसरे दिन प्रत्येक को हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषाओं में निष्पन्न किया गया है, दोनों पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं । अर्थ निरूपण में भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ प्रभावी माना जाएगा ।

भारत गणराज्य की
सरकार की ओर से

(के. रामालिंगम)
संयुक्त सचिव
विदेश कर एवं कर अनुसंधान प्रभाग
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व विभाग
वित्त मंत्रालय

लाइबेरिया गणराज्य की
सरकार की ओर से

(आगस्टाइन के. नाफुआन)
वित्त मंत्री
लाइबेरिया

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th August, 2012

(INCOME-TAX)

S.O. 1877(E).— Whereas the annexed Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Liberia for the exchange of information and assistance in collection with respect to taxes was signed in Liberia on the 3rd day of October, 2011;

And whereas the date of entry into force of said agreement is the 30th day of March 2012, being the date of the later of the notifications after completion of the procedures as required by the respective laws for the entry into force of this Agreement, in accordance with article 12 of the said Agreement;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies that all the provisions of the said Agreement annexed hereto shall be given effect to in the Union of India with effect from the 30th day of March, 2012.

[Notification No. 32/20012-FT&TR-II/F.No. 503/02/2010-FT&TR-II]

K. RAMALINGAM, Jt. Secy.

**AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LIBERIA
FOR
THE EXCHANGE OF INFORMATION
AND
ASSISTANCE IN COLLECTION
WITH RESPECT TO TAXES**

The Government of the Republic of India and the Government of Republic of Liberia, desiring to facilitate the exchange of information and assistance in collection with respect to taxes have agreed as follows:

Article 1
Object and Scope of the Agreement

The competent authorities of the Contracting Parties shall provide assistance through exchange of information that is foreseeably relevant to the administration and enforcement of the domestic laws of the Contracting Parties concerning taxes covered by this Agreement. Such information shall include information that is foreseeably relevant to the determination, assessment and collection of such taxes, the recovery and enforcement of tax claims, or the investigation or prosecution of tax matters. Information shall be exchanged in accordance with the provisions of this Agreement. The competent authorities shall also lend assistance to each other in the collection of tax claims. The rights and safeguards secured to persons by the laws or administrative practice of the requested Party remain applicable to the extent that they do not unduly prevent or delay effective exchange of information or assistance in collection.

Article 2
Jurisdiction

Information shall be exchanged in accordance with this Agreement without regard to whether the person to whom the information relates is, or whether the information is held by, a resident of a Contracting Party. However, a Requested Party is not obliged to provide information which is neither held by its authorities nor is in the possession or control of persons who are within its territorial jurisdiction.

Article 3
Taxes Covered

1. The taxes which are the subject of this Agreement are taxes of every kind and description imposed by the Contracting Parties at the date of signature of the Agreement.
2. This Agreement shall also apply to any identical or substantially similar taxes imposed after the date of signature of this Agreement in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting Parties shall notify each other of any substantial changes to the taxation and related information gathering measures and assistance in collection measures which may affect the obligations of that Party pursuant to this Agreement.

Article 4
Definitions

1. For the purposes of this Agreement, unless otherwise defined:
 - (a) the term "India" means the territory of India and includes the territorial sea and airspace above it, as well as any other maritime zone in which India has sovereign rights, other rights and jurisdiction, according to the Indian law and in accordance with international law, including the U.N. Convention on the Law of the Sea;
 - (b) the term "Liberia" means the Republic of Liberia situated and located in West Africa, including its territorial seas and any area beyond the territorial sea within which Liberia, in accordance with International Law, exercises jurisdiction;
 - (c) the term "Contracting Party" means India or Liberia as the context requires;
 - (d) the term "competent authority" means
 - (i) in the case of India, the Finance Minister, Government of India, or his authorised representative;
 - (ii) in the case of Liberia, the Minister of Finance or his authorised representative;
 - (e) the term "person" includes an individual, a company, a body of persons and any other entity which is treated as a taxable unit under the taxation laws in force in the respective Contracting Parties;
 - (f) the term "company" means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes;
 - (g) the term "publicly traded company" means any company whose principal class of shares is listed on a recognised stock exchange provided its listed

30836112-5

shares can be readily purchased or sold by the public. Shares can be purchased or sold "by the public" if the purchase or sale of shares is not implicitly or explicitly restricted to a limited group of investors;

(h) the term "principal class of shares" means the class or classes of shares representing a majority of the voting power and value of the company;

(i) the term "recognised stock exchange" means any stock exchange agreed upon by the competent authorities of the Contracting Parties;

(j) the term "collective investment fund or scheme" means any pooled investment vehicle, irrespective of legal form.

(k) the term "public collective investment fund or scheme" means any collective investment fund or scheme provided the units, shares or other interests in the fund or scheme can be readily purchased, sold or redeemed by the public. Units, shares or other interests in the fund or scheme can be readily purchased, sold or redeemed "by the public" if the purchase, sale or redemption is not implicitly or explicitly restricted to a limited group of investors;

(l) the term "tax" means any tax to which this Agreement applies;

(m) the term "requesting Party" means the Contracting Party—

- (i) submitting a request for information to, or
- (ii) having received information from, or
- (iii) submitting a request for assistance in collection of tax to,

the requested Party.

(n) the term "requested Party" means the Contracting Party—

- (i) which is requested to provide information, or
- (ii) which has provided information, or
- (iii) which is requested to provide assistance in collection of tax.

(o) the term "information gathering measures" means laws and administrative or judicial procedures that enable a Contracting Party to obtain and provide the requested information;

(p) the term "assistance in collection measures" means laws and administrative or judicial procedures that enable a Contracting Party to collect and remit the requested tax claim;

(q) the term "information" means any fact, statement, document or record in whatever form;

2. As regards the application of this Agreement at any time by a Contracting Party, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires

or the competent authorities agree to a common meaning pursuant to the provisions of Article 10 of this Agreement, have the meaning that it has at that time under the law of that Party, any meaning under the applicable tax laws of that Party prevailing over a meaning given to the term under other laws of that Party.

Article 5
Exchange of Information Upon Request

1. The competent authority of the requested Party shall provide upon request information for the purposes referred to in Article 1. Such information shall be exchanged without regard to whether the requested Party needs such information for its own tax purposes or whether the conduct being investigated would constitute a crime under the laws of the requested Party if such conduct occurred in the requested Party.

2. If the information in the possession of the competent authority of the requested Party is not sufficient to enable it to comply with the request for information, that Party shall use all relevant information gathering measures to provide the requesting Party with the information requested, notwithstanding that the requested Party may not need such information for its own tax purposes.

3. If specifically requested by the competent authority of the requesting Party, the competent authority of the requested Party shall provide information under this Article, to the extent allowable under its domestic laws, in the form of depositions of witnesses and authenticated copies of original records.

4. Each Contracting Party shall ensure that its competent authority, for the purposes of this Agreement, has the authority to obtain and provide upon request:

(a) information held by banks, other financial institutions, and any person, including nominees and trustees, acting in an agency or fiduciary capacity;

(b) information regarding the legal and beneficial ownership of companies, partnerships, collective investment funds or schemes, trusts, foundations, "Anstalten" and other persons, including, within the constraints of Article 2, ownership information on all such persons in an ownership chain; in the case of collective investment funds or schemes, information on shares, units and other interests; in the case of trusts, information on settlors, trustees and beneficiaries; in the case of foundations, information on founders, members of the foundation council and beneficiaries; and equivalent information in case of entities that are neither trusts nor foundations.

5. This Agreement does not create an obligation on the Contracting Parties to obtain or provide ownership information with respect to publicly traded companies or public collective investment funds or schemes unless such information can be obtained without giving rise to disproportionate difficulties.

6. The competent authority of the requesting Party shall provide the following information to the competent authority of the requested Party when making a request for information under the Agreement to demonstrate the foreseeable relevance of the information to the request:

- (a) the identity of the person under examination or investigation;
- (b) the period for which information is requested;
- (c) the nature of the information requested and the form in which the requesting Party would prefer to receive it ;
- (d) the tax purpose for which the information is sought;
- (e) grounds for believing that the information requested is present in the requested Party or is in the possession or control of a person within the jurisdiction of the requested Party;
- (f) to the extent known, the name and address of any person believed to be in possession or control of the requested information;
- (g) a statement that the request is in conformity with the laws and administrative practices of the requesting Party, that if the requested information was within the jurisdiction of the requesting Party then the competent authority of the requesting Party would be able to obtain the information under the laws of the requesting Party or in the normal course of administrative practice and that it is in conformity with this Agreement;
- (h) a statement that the requesting Party has pursued all means available in its own territory to obtain the information, except those that would give rise to disproportionate difficulties.

7. The competent authority of the requested Party shall forward the requested information as promptly as possible to the requesting Party. To ensure a prompt response, the competent authority of the requested Party shall:

- (a) Confirm receipt of a request in writing to the competent authority of the requesting Party and shall notify the competent authority of the requesting Party of deficiencies in the request, if any, within 60 days of the receipt of the request.
- (b) If the competent authority of the requested Party has been unable to obtain and provide the information within 90 days of receipt of the request, including if it encounters obstacles in furnishing the information or it refuses to furnish the information, it shall immediately inform the requesting Party, explaining the reason for its inability, the nature of the obstacles or the reasons for its refusal.

Article 6
Tax Examinations Abroad

1. At the request of the competent authority of the requesting Party, the requested Party may allow representatives of the competent authority of the requesting Party to enter the territory of the requested Party, to the extent permitted under its domestic laws, to interview individuals and examine records with the prior written consent of the individuals or other persons concerned. The competent authority of the requesting Party shall notify the competent authority of the requested Party of the time and place of the intended meeting with the individuals concerned.
2. At the request of the competent authority of the requesting Party, the requested Party may allow representatives of the competent authority of the requesting Party to be present at the appropriate part of a tax examination in the requested Party, in which case the competent authority of the requested Party conducting the examination shall, as soon as possible, notify the competent authority of the requesting Party about the time and place of the examination, the authority or official designated to carry out the examination and the procedures and conditions required by the requested Party for the conduct of the examination. All decisions with respect to the conduct of the tax examination shall be made by the Party conducting the examination.

Article 7
Possibility of Declining a Request for information

1. The competent authority of the requested Party may decline to assist:
 - (a) where the request is not made in conformity with this Agreement; or
 - (b) where the requesting Party has not pursued all means available in its own territory to obtain the information, except where recourse to such means would give rise to disproportionate difficulty; or
 - (c) where disclosure of the information would be contrary to public policy (ordre public) of the requested Party.
2. This Agreement shall not impose on a Contracting Party the obligation:
 - (i) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, provided that information described in paragraph 4 of Article 5 shall not be treated as such a secret or trade process merely because it meets the criteria in that paragraph; or
 - (ii) to obtain or provide information, which would reveal confidential communications between a client and an attorney, solicitor or other admitted legal representative where such communications are:

- (a) produced for the purposes of seeking or providing legal advice or
- (b) produced for the purposes of use in existing or contemplated legal proceedings; or

(iii) to carry out administrative measures at variance with its laws and administrative practices, provided nothing in this subparagraph shall affect the obligations of a Contracting Party under paragraph 4 of Article 5.

3. A request for information shall not be refused on the ground that the tax claim giving rise to the request is disputed.

4. The requested Party shall not be required to obtain and provide information which the requesting Party would be unable to obtain in similar circumstances under its own laws for the purpose of the administration or enforcement of its own tax laws or in response to a valid request from the requested Party under this Agreement.

5. The requested Party shall not decline to provide information solely because the request does not include all the information required under Article 5 if the information can otherwise be provided according to the law of the requested Party.

Article 8 **Assistance in the Collection of Tax Claims**

1. The Contracting Parties shall lend assistance to each other in the collection of tax claims.

2. The term "tax claim" as used in this Article means an amount owed in respect of taxes as mentioned in Article 3, as well as interest, administrative penalties and costs of collection or conservancy related to such amount.

3. When a tax claim of a Contracting Party is enforceable under the laws of that Party and is owed by a person who, at that time, cannot, under the laws of that Party, prevent its collection, that tax claim shall, at the request of the competent authority of that Party, be accepted for purposes of collection by the competent authority of the other Contracting Party. That tax claim shall be collected by that other Party in accordance with the provisions of its laws applicable to the enforcement and collection of its own taxes as if the tax claim were a tax claim of that other Party.

4. When a tax claim of a Contracting Party is a claim in respect of which that Party may, under its law, take measures of conservancy with a view to ensure its collection, that tax claim shall, at the request of the competent authority of that Party, be accepted for purposes of taking measures of conservancy by the competent authority of the other Contracting Party. That other Party shall take measures of conservancy in respect of that tax claim in accordance with the provisions of its laws as if the tax claim were a tax claim of

that other Party even if, at the time when such measures are applied, the tax claim is not enforceable in the first-mentioned Party or is owed by a person who has a right to prevent its collection.

5. When a Contracting Party, under its law, takes interim measures of conservancy by freezing of assets before a tax claim is raised against a person, the competent authority of the other Contracting Party if requested by the competent authority of the first-mentioned Contracting Party shall take measures for freezing the assets of that person in that Contracting Party in accordance with the provisions of its law.

6. Notwithstanding the provisions of paragraphs 3 and 4, a tax claim accepted by a Contracting Party for purposes of paragraph 3 or 4 shall not, in that State, be subject to the time limits or accorded any priority applicable to a tax claim under the laws of that State by reason of its nature as such. In addition, a tax claim accepted by a Contracting Party for the purposes of paragraph 3 or 4 shall not, in that State, have any priority applicable to that tax claim under the laws of the other Contracting Party.

7. Proceedings with respect to the existence, validity or the amount of a tax claim of a Contracting Party shall only be brought before the courts or administrative bodies of that Party. Nothing in this Article shall be construed as creating or providing any right to such proceedings before any court or administrative body of the other Contracting Party.

8. Where, at any time after a request has been made by a Contracting Party under paragraph 3 or 4 and before the other Contracting Party has collected and remitted the relevant tax claim to the first-mentioned Party, the relevant tax claim ceases to be:

a) in the case of a request under paragraph 3, a tax claim of the first-mentioned Party that is enforceable under the laws of that Party and is owed by a person who, at that time, cannot, under the laws of that Party, prevent its collection, or

b) in the case of a request under paragraph 4, a tax claim of the first-mentioned Party in respect of which that Party may, under its laws, take measures of conservancy with a view to ensure its collection,

the competent authority of the first-mentioned Party shall promptly notify the competent authority of the other Party of that fact and, at the option of the other Party, the first-mentioned Party shall either suspend or withdraw its request.

9. In no case shall the provisions of this Article be construed so as to impose on a Contracting Party the obligation:

a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting Party;

b) to carry out measures which would be contrary to public policy (ordre public);

c) to provide assistance if the other Contracting Party has not pursued all reasonable measures of collection or conservancy, as the case may be, available under its laws or administrative practice;

to provide assistance in those cases where the administrative burden for that State is clearly disproportionate to the benefit to be derived by the other Contracting Party.

Article 9
Implementation Legislation

The Contracting Parties shall enact any legislation necessary to comply with, and give effect to, the terms of the Agreement. Such legislation shall be enacted within six months of entry into force of this Agreement.

Article 10
Costs

Incidence of costs incurred in providing assistance shall be agreed by the Contracting Parties.

Article 11
Mutual Agreement Procedure

1. Where difficulties or doubts arise between the Contracting Parties regarding the implementation or interpretation of the Agreement, the competent authorities shall endeavour to resolve the matter by mutual agreement. In addition, the competent authorities of the Contracting Parties may mutually agree on the procedures to be used under Articles 5, 6 and 8 of this Agreement.

2. The competent authorities of the Contracting Parties may communicate with each other directly for purposes of reaching agreement under this Article.

Article 12
Entry into Force

1. The Contracting Parties shall notify each other in writing, through diplomatic channels, of the completion of the procedures required by the respective laws for the entry into force of this Agreement.

2. This Agreement shall enter into force on the date of the later of the notifications referred to in paragraph 1 of this Article and shall thereupon have effect forthwith.

Article 13
Termination

1. This Agreement shall remain in force until terminated by either Contracting Party.
2. Either Contracting Party may, after the expiry of five years from the date of its entry into force, terminate the Agreement by serving a written notice of termination to the other Contracting Party through diplomatic channels.
3. Such termination shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of six months after the date of receipt of notice of termination by the other Contracting Party. All requests received up to the effective date of termination shall be dealt with in accordance with the provisions of the Agreement.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Agreement.

DONE in duplicate at Monrovia this Third day of October, 2011, each in the English and Hindi languages, both texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of the
Republic of India

(K. RAMALINGAM)
Joint Secretary
Foreign Tax & Tax Research
Central Board of Direct Taxes
Department of Revenue
Ministry of Finance

For the Government of the
Republic of Liberia

(AUGUSTINE K. NGAIUAN)
Minister of Finance